कीटनाशी : केन्द्रीय सरकार ने फरीदाबाद में एक केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला स्थापित की है जिसकी एक शाखा वनस्पति संगरोध और धूमीकरण केन्द्र, बम्बई और दूसरी शाखा केन्द्रीय वनस्पति संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में है ताकि कीटनाशियों के गुणवत्ता स्तर को सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशियों के नमूनों का परीक्षण करने में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की मदद की जा सके । इसके अतिरिक्त, इस संबंध में राज्य सरकारों के संसाधनों के पूरक के रूप में बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद और कानपुर में 5 क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं । 18 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र ने प्रति वर्ष लगभग 34,000 नमूनों की क्षमता वाली 35 कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं पहले ही स्थापित कर ली हैं ।

Subsidy for foodgrains

2811. SHRI SHANKER SINH VAGHELA:

SHRI ASHWANI KUMAR;

SHRI KAILASH PATI MISHRA;

Will the . Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES he pleased to state:

(a) what is the amount of subsidy given for foodgrains during the last three years, year-wise and during the current year;

(b) what are the estimates in regard to increase or decrease in the amount of subsidy for the next three years; and

(c) what was the average amount of subsidy given since the inception of the scheme?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH); (a) The provision for food subsidy made in the Budget of the Department of Food during the last three years and the current year (BE-1985-86) is indicated below

(Rs- in Crores)

Year	Budget Provision
1982-83	710·00
1983-84	835·00
1984-85	1100·00
1985-86	1100·00

(b) It is difficult to anticipate the variation in the amount of subsidy during the next three years, as the amount would depend on many factors, e. g. quantum of off-take, rate of various taxes, rail and road freight, rate of landing charges in case of imports, storage charges, administrative over-heads, handling expenses, support price and the issue price notified by the Government, etc.

(c) The average subsidy from 1969-70 to 1984-85 is Rs. 443.12 crores per year.

Indo-US collaboration in agricultural development

2812. SHRI R. SAMBASIVA RAO: Will the Minister of AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India and the United States have recently decided to collaborate in assisting the third world countries in their agricultural development programmes; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI CHANDU-LAL CHANDRAKAR): (a) Yes, Sir.

(b) The details are yet to be worked out by the two counrties mutually.

Installation of water meters in Moti Bagh, New Delhi

2813. SHRI SYED AHMAD HASHMI; Will the Minister of WORKS AND HOUSING toe pleased to state:

(a) whether it is a fact that water meters have been stolen from the quarters of Moti Bagh, New Delhi, whether it is also a fact that the N.D.M.C. has asked the residents to deposit Rs. 150 for these water met-ters and in spite of depositing the amount by them no meter has been reinstalled in their quarters and the money deposited for this purpose has lot been returned to them so far; and

(b) if so, what are the reasons therefor and how much time will be taken to return the deposit after installation of water meres?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT); (a) and (b) The NDMC have informed that in cases where water meters are stolen the residents are required to deposit a sum of Rs. 150 in each case with the Committee as cost of a stolen meter. There are cases where the residents have deposited the cost of stolen water meters with the NDMC but the meter$_s$ have not yet been insialled. NDMC are reported to be awaiting reports from the CPWD regarding shifting of meter chambers inside the quarters in these cases. The CPWD have been advised to expedite shifting of the meter chambers quickly. The cost of water meters deposited by the residents with the NDMC will be reimbursed by the CPWD to the allottees immediately after installation report is received by them from TDMC.

मोती बाग, नई दिल्ली में 80 वर्ग गज वाले प्लाट

2314. **श्री धलेश्वर मीणा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोती बाग जे० जे० कालोनी में 80 वर्ग गज के प्लाटों की कुल संख्या कितनी है और इन प्लाटों के मूल आवंटितियों और खरीददारों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्लाटधारियों ने अनधिकृत रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा कर लिया है और उस पर बगीचे लगा लिए हैं ; यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन्हें सरकारी भूमि पर बगीचे लगाने की अनुमति दे दी थी और यदि नहीं तो क्या उनसे सरकारी भूमि को वापिस ले लिया जाएगा ; और

(ग) इस भूमि पर कुल कितने नये प्लाटों के काटे जाने की संभावना है और सरकार को इससे कितना आर्थिक लाभ होगा ;

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) इस कालोनी में 80 वर्ग गज से लेकर 92 वर्ग गज तक विभिन्न आकारों के 299 प्लाट हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मूल आवंटितियों और अनधिकृत खरीददारों की संख्या का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । 1981–82 में किये गये एक छोटे सर्वेक्षण के अनुसार इस कालोनी में मात्र 46 मूल आवंटी थे ।

(ख) कुछ दखलकारों ने अपने प्लाटों से लगी भमि पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमति लिये बिना ही बगीचे बना लिये हैं और कानून के अनुसार इन अतिक्रमणों को हटाया जा सकता है ।

(ग) इस कालोनी में नये प्लाट काटने की दिल्ली विकास प्राधिकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।